KGS IAS

Current Affairs

UPSC Prelims 2024

LECTURE-12

By Kinshuk Sir

KGS IAS

KHAN GLOBAL STUDIES

Most Trusted Learning Platform

KHAN SIR

Most Trusted Learning Platform

CURRENT AFFAIRS DISCUSSION

❖ CDP SURAKSHA

- **Syllabus:** GS Paper III
- **Context:** The government has come up with a new platform to disburse subsidies to horticulture farmers under the Cluster Development Programme (CDP) — the Centre's initiative to promote horticulture crops

❖ सीडीपी सुरक्षा

- **पाठ्यक्रम:** जीएस पेपर III
- **संदर्भ:** सरकार क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी) के तहत बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए एक नया मंच लेकर आई है - बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की पहल

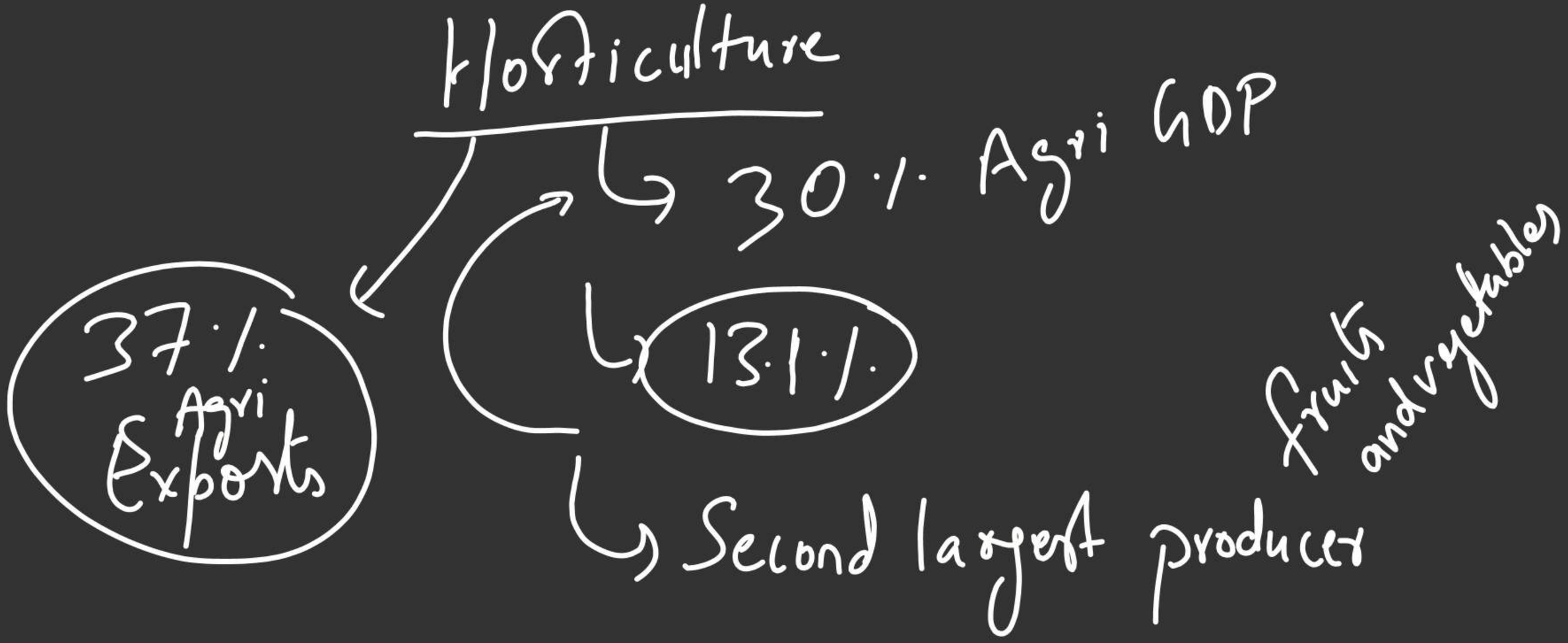
Horticulture
30% Agri GDP
13.1%
37.1% Agri Exports
Second largest producer
fruits and vegetables

Horticulture in India:

- At present, India is the second largest producer of vegetables and fruits in the world.
- India ranks first in the production of number of crops like Banana, Lime & Lemon, Papaya, Okra.
- Horticulture contributes 30.4% of India's agriculture Gross Domestic Product (GDP) using only 13.1% of the country's gross cropped area.

भारत में बागवानी:

- वर्तमान समय में भारत दुनिया में सब्जियों और फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
- केला, निम्बू और नींबू, पपीता, भिंडी जैसी कई फसलों के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है।
- बागवानी भारत के कृषि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 30.4% का योगदान देती है और देश के सकल फसल क्षेत्र का केवल 13.1% उपयोग करती है।
- भारत से दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कृषि वस्तुओं के कुल निर्यात में बागवानी क्षेत्र का हिस्सा लगभग 37% है।

- The horticulture sector accounts for about 37% of the total exports of agricultural commodities from India to different parts of the world
- What is the CDP-SURAKSHA?
- SURAKSHA stands for "System for Unified Resource Allocation, Knowledge, and Secure Horticulture Assistance."
- The digital platform will allow an instant disbursal of subsidies to farmers in their bank account by utilising the e-RUPI voucher from the National Payments Corporation of India (NPCI).

- सीडीपी-सुरक्षा क्या है?
- सुरक्षा का अर्थ है "एकीकृत संसाधन आवंटन, ज्ञान और सुरक्षित बागवानी सहायता के लिए प्रणाली।"
- डिजिटल प्लेटफॉर्म नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) से e-RUPI वाउचर का उपयोग करके किसानों को उनके बैंक खाते में तुरंत सब्सिडी देने की अनुमति देगा।

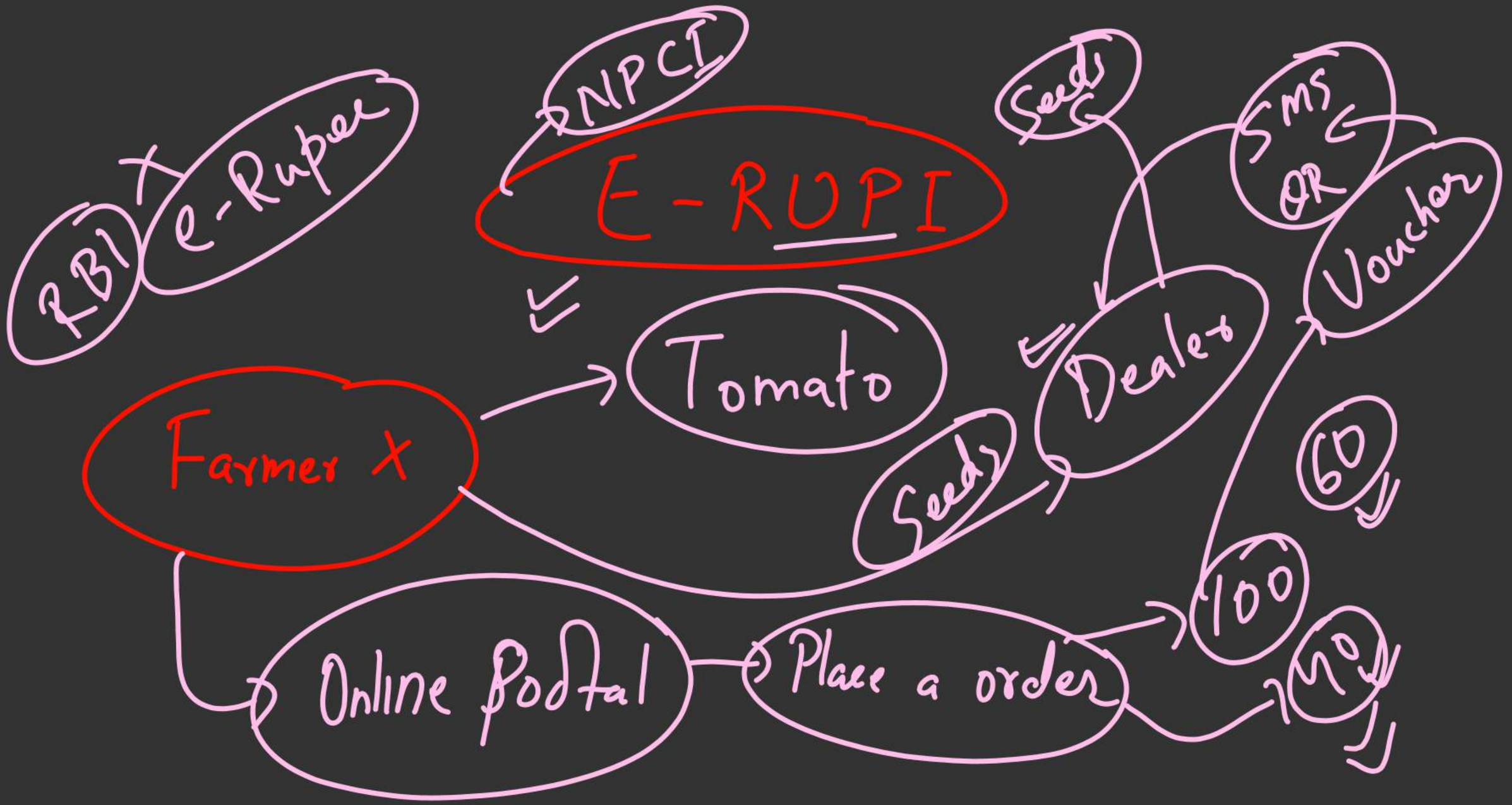
RBI
e-Rupee
NPCI
E-RUPI
Seeds
SMS OR
Voucher
Tomato
Farmer X
Dealer
Seeds
60
Online Portal
Place a order
100
40

Horticulture benefits

→ Environment friendly - Sequester more carbon

→ Nutritious food in comparison to Cereal crops.

→ higher contribution to GDP/Exports.

→ higher profitability for farmers.

Challenge

Subsidy + loan ⟷ Capital Intensive

Agroforestry ⟷ large tracts of land is required

(PMKISAN)

Alternate emp opportunity ⟷ No returns in short term

→ lack of skill and knowledge.

CDP SURAKSHA ←

- **How does the CDP-SURAKSHA work?**
- **The platform allows access to farmers, vendors, implementing agencies (IA), and cluster development agencies (CDAs), and officials of the National Horticulture Board (NHB).**
- **A farmer can login using their mobile number and place an order for planting material such as seeds, seedlings, and plants based on their requirement.**

- **सीडीपी-सुरक्षा कैसे काम करती है?**
- यह मंच किसानों, विक्रेताओं, कार्यान्वयन एजेंसियों (IA), और क्लस्टर विकास एजेंसियों (सीडीए), और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) के अधिकारियों तक पहुंच की अनुमति देता है।
- एक किसान अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके लॉगिन कर सकता है और अपनी आवश्यकता के आधार पर बीज, पौध और पौधे जैसी रोपण सामग्री के लिए ऑर्डर दे सकता है।

- Once the farmer has raised the demand, the system will ask them to contribute their share of the cost of planting material. The subsidy amount paid by the government will appear on the screen automatically.
- After the farmer pays their contribution, an e-RUPI voucher will be generated. This voucher will then be received by a vendor, who will provide the required planting material to the farmer.

- एक बार जब किसान ने मांग उठाई, तो सिस्टम उनसे रोपण सामग्री की लागत में अपना हिस्सा देने के लिए कहेगा। सरकार द्वारा भुगतान की गई सब्सिडी राशि स्वचालित रूप से स्क्रीन पर दिखाई देगी।
- किसान द्वारा अपना योगदान देने के बाद एक e-RUPI वाउचर जेनरेट होगा। यह वाउचर फिर एक विक्रेता को प्राप्त होगा, जो किसान को आवश्यक रोपण सामग्री प्रदान करेगा।

- Once the ordered planting material is delivered to the farmer, they have to verify the delivery through geo-tagged photos and videos of their field. It is only after the verification that the IA will release the money to the vendor for the e-RUPI voucher.
- The vendor will be required to upload an invoice of the payment on the portal.
- The IA will collect all the documents and share them with the CDA for subsidy release, then only the subsidy will be released to the IA.

- एक बार ऑर्डर की गई रोपण सामग्री किसान तक पहुंचा दी जाती है, तो उन्हें अपने खेत की जियो-टैग की गई तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से डिलीवरी को सत्यापित करना होगा। सत्यापन के बाद ही IA विक्रेता को e-RUPI वाउचर के लिए पैसा जारी करेगा।
- विक्रेता को भुगतान का चालान पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- IA सभी दस्तावेज एकत्र करेगा और सब्सिडी जारी करने के लिए उन्हें सीडीए के साथ साझा करेगा, उसके बाद ही IA को सब्सिडी जारी की जाएगी।

- **What is e-RUPI?**
- The CDP-SURAKSHA platform uses e-RUPI vouchers from the NPCI.
- e-RUPI is basically a digital voucher which a beneficiary gets on his phone in the form of an SMS or QR code.
- It is a pre-paid voucher, which he/she can go and redeem it at any centre that accepts it.
- For example, if the Government wants to cover a particular treatment of an employee

- **e-RUPI क्या है?**
- सीडीपी-सुरक्षा प्लेटफॉर्म एनपीसीआई के e-RUPI वाउचर का उपयोग करता है।
- e-RUPI मूल रूप से एक डिजिटल वाउचर है जो लाभार्थी को एसएमएस या क्यूआर कोड के रूप में उसके फोन पर मिलता है।
- यह एक प्री-पेड वाउचर है, जिसे वह स्वीकार करने वाले किसी भी केंद्र पर जाकर भुना सकता है।
- उदाहरण के लिए, यदि सरकार किसी निर्दिष्ट अस्पताल में किसी कर्मचारी के विशेष उपचार को कवर करना चाहती है, तो वह एक भागीदार बैंक के माध्यम से निर्धारित राशि के लिए e-RUPI वाउचर जारी कर सकती है।

- in a specified hospital, it can issue an e-RUPI voucher for the determined amount through a partner bank.
- The employee will receive an SMS or a QR Code on his feature phone/smartphone. He/she can go to the specified hospital, avail of the services and pay through the e-RUPI voucher received on his phone.
- Thus e-RUPI is a one-time contactless, cashless voucher-based mode of payment that helps users redeem the voucher without a card, digital payments app, or internet banking access.

- कर्मचारी को उसके फीचर फोन/स्मार्टफोन पर एक एसएमएस या एक क्यूआर कोड प्राप्त होगा। वह निर्दिष्ट अस्पताल में जा सकता है, सेवाओं का लाभ उठा सकता है और अपने फोन पर प्राप्त e-RUPI वाउचर के माध्यम से भुगतान कर सकता है।
- इस प्रकार e-RUPI एक बार संपर्क रहित, कैशलेस वाउचर-आधारित भुगतान का तरीका है जो उपयोगकर्ताओं को कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस के बिना वाउचर को भुनाने में मदद करता है।
- e-RUPI को डिजिटल करेंसी के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक विचार कर रहा है।

- e-RUPI should not be confused with Digital Currency which the Reserve Bank of India is contemplating. Instead, e-RUPI is a person-specific, even purpose-specific digital voucher.
- e-RUPI does not require the beneficiary to have a bank account, a major distinguishing feature as compared to other digital payment forms.
- It ensures an easy, contactless two-step redemption process that does not require the sharing of personal details either.

- इसके बजाय, e-RUPI एक व्यक्ति-विशिष्ट, यहां तक कि उद्देश्य-विशिष्ट डिजिटल वाउचर है।
- e-RUPI के लिए लाभार्थी के पास बैंक खाता होना आवश्यक नहीं है, जो अन्य डिजिटल भुगतान रूपों की तुलना में एक प्रमुख विशेषता है।
- यह एक आसान, संपर्क रहित दो-चरणीय मोचन प्रक्रिया सुनिश्चित करता है जिसमें व्यक्तिगत विवरण साझा करने की भी आवश्यकता नहीं होती है।
- एक और फायदा यह है कि e-RUPI बेसिक फोन पर भी संचालित होता है, और इसलिए इसका उपयोग उन लोगों द्वारा किया जा सकता है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या उन जगहों पर जहां इंटरनेट कनेक्शन की कमी है।

- Another advantage is that e-RUPI is operable on basic phones also, and hence it can be used by persons who do not own smartphones or in places that lack internet connection.
- It has been developed by NPCI and can be issued by many Public and Private Scheduled Commerical banks authorised by NPCI

- इसे एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया है और इसे एनपीसीआई द्वारा अधिकृत कई सार्वजनिक और निजी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी किया जा सकता है

❖ Women's Participation in the Workforce:

➢ **Syllabus:** GS Paper I/II

➢ **Some Facts about Financial Involvement of Women in India**

➢ As per the periodic labour force survey participation of women in the labour force has risen to 37 per cent in 2022-23 from 23.3 per cent in 2017-18.

➢ A survey done in October 2023, suggests that the urban labour force has grown from 20.4 per cent in 2017-18 to 25.4 per cent in 2022-23,

❖ कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी:

➢ **पाठ्यक्रम:** जीएस पेपर I/II

➢ **भारत में महिलाओं की वित्तीय भागीदारी के बारे में कुछ तथ्य**

➢ आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी 2017-18 में 23.3 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 37 प्रतिशत हो गई है।

➢ अक्टूबर 2023 में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि शहरी श्रम शक्ति 2017-18 में 20.4 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 25.4 प्रतिशत हो गई है।

- The rural women's labour force has grown at a much faster rate from 24.6 per cent to 41.5 per cent during the same five years.
- If we talk about the income source of working women in India, 55 per cent are self-employed while 39 per cent are salaried.
- Seeing the working women in age brackets suggests, 41 per cent of women between the age group of 25-35 years are working.
- Surprisingly 49 per cent of women between the age group of 36-45 are working and

- उन्हीं पाँच वर्षों के दौरान ग्रामीण महिलाओं की श्रम शक्ति 24.6 प्रतिशत से बढ़कर 41.5 प्रतिशत हो गई है।
- अगर भारत में कामकाजी महिलाओं के आय स्रोत की बात करें तो 55 प्रतिशत स्व-रोज़गार हैं जबकि 39 प्रतिशत वेतनभोगी हैं।
- आयु वर्ग में कामकाजी महिलाओं को देखने से पता चलता है कि 25-35 वर्ष की आयु वर्ग की 41 प्रतिशत महिलाएँ कामकाजी हैं।
- आश्चर्यजनक रूप से 36-45 आयु वर्ग की 49 प्रतिशत महिलाएं कामकाजी हैं और 45 वर्ष से अधिक उम्र की 65 प्रतिशत से अधिक महिलाएं कामकाजी हैं।

- over 65 per cent of women above the age of 45 years are working.
- The report suggests more working women in the mid and higher age group are from rural areas.
- As per the report, women invest 15 per cent of their savings in mutual funds, which is higher than the overall household savings allocation to mutual funds at 8.4 per cent.
- Women also invested 51 per cent of their savings in fixed deposits versus 46 per cent for overall households.

- रिपोर्ट बताती है कि मध्य और उच्च आयु वर्ग की अधिक कामकाजी महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों से हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, महिलाएं अपनी बचत का 15 प्रतिशत म्यूचुअल फंड में निवेश करती हैं, जो कि म्यूचुअल फंड में कुल घरेलू बचत आवंटन 8.4 प्रतिशत से अधिक है।
- महिलाओं ने अपनी बचत का 51 प्रतिशत सावधि जमा में भी निवेश किया, जबकि समग्र परिवारों के लिए यह 46 प्रतिशत था।
- लगभग 98 प्रतिशत शहरी महिलाएँ घरेलू वित्तीय निवेश सहित दीर्घकालिक पारिवारिक निर्णय लेने में शामिल हैं।

- About 98 per cent of urban women are involved in making long-term family decisions, including household financial investments.
- Why do Women have lesser representation in the Workforce?

- कार्यबल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम क्यों है?

Figure 4: Reasons reported by females (in %) for not being in labour force

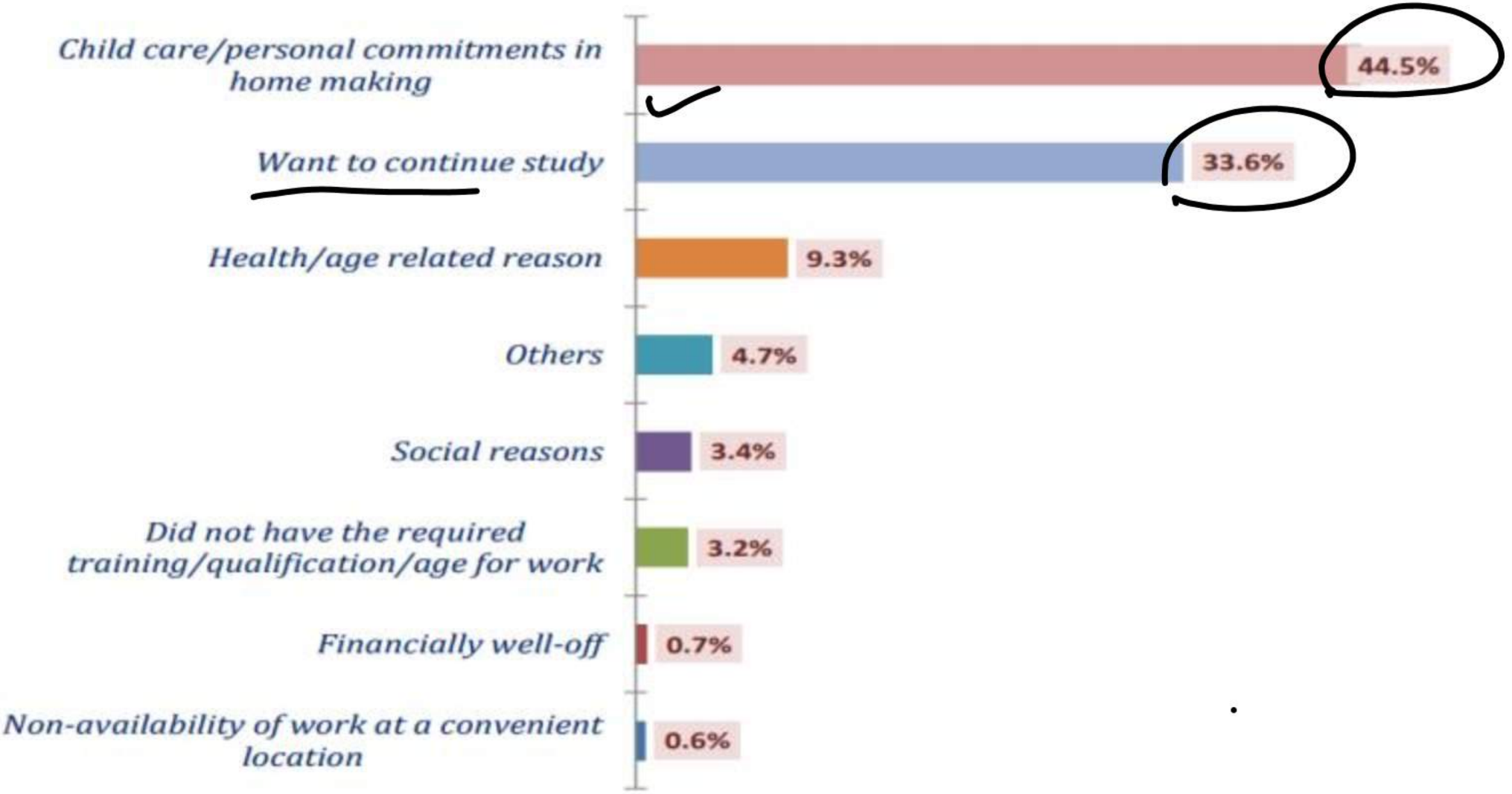

- **Government Steps for Encouraging women**
- **Beti Bachao Beti Padhao Scheme:** The scheme was launched for creating awareness among the people to educate all girl children in the country. It was launched with the objective to guarantee the survival, safety, and education of female children
- **National Education Policy (NEP), 2020:** The policy prioritises gender equity and envisions ensuring equitable access to quality education to all students, with a special emphasis on Socially and

- **महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के कदम**
- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना:** देश में सभी बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। इसे महिला बच्चों के अस्तित्व, सुरक्षा और शिक्षा की गारंटी देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020:** यह नीति लैंगिक समानता को प्राथमिकता देती है और सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) पर विशेष जोर देने के साथ सभी छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने की परिकल्पना करती है।

- Economically Disadvantaged Groups (SEDGs).
- Establishment of Working Women Hostel through grant-in-aid by the government across various cities of India.
- Establishment of One Stop Centre (OSC) and Universalization of Women Helpline
- Passing of Prevention of Sexual Harassment at Workplace Act 2013.

- भारत के विभिन्न शहरों में सरकार द्वारा अनुदान सहायता के माध्यम से कामकाजी महिला छात्रावास की स्थापना।
- वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) की स्थापना और महिला हेल्पलाइन का सार्वभौमिकरण
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013 का पारित होना।

- Enhancement in paid maternity leave from 12 weeks to 26 weeks, Maternity leave of 12 weeks to mothers adopting a child below the age of three months as well as to the commissioning mothers, provision for mandatory crèche facility in the establishments having 50 or more employees
- The Code on Wages, 2019 provides that there shall be no discrimination in an establishment or any unit thereof among employees on the ground of gender in matters relating to wages by the same

- सवैतनिक मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना, तीन महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली माताओं के साथ-साथ कमीशनिंग माताओं के लिए 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश, 50 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा का प्रावधान।
- वेतन संहिता, 2019 में प्रावधान है कि किसी प्रतिष्ठान या उसकी किसी इकाई में कर्मचारियों के बीच समान नियोक्ता द्वारा वेतन से संबंधित मामलों में, समान काम या समान प्रकृति के काम के संबंध में लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

- employer, in respect of the same work or work of similar nature done by any employee
- The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (MGNREGA) mandates that at least one third of the jobs generated under the scheme (MGNREGS) should be given to women.

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (मनरेगा) कहता है कि योजना (मनरेगा) के तहत उत्पन्न कम से कम एक तिहाई नौकरियां महिलाओं को दी जानी चाहिए।

MISSION SHAKTI
Ministry of Women and Child Development
Government of India
Women Helpline (181-WHL)
Beti Bachao Beti Padhao
One Stop Centres (OSC)
Nari Adalats
'Sambal'
Safety and Security of Women
Swadhar Greh
Working Women Hostel
National Creche Scheme
Ujjwala
Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana
'Samarthya'
Empowerment of Women

- **Way Forward**
- **Double Shift Burden:** 3Rs approach, which involves Recognizing, Reducing, and Redistributing the unpaid care work done by women in all areas of policymaking.
- **Care Economy:** There is a need to reconceptualize the CARE economy in India. It is estimated that with public investment of just 2% of India's GDP in the care economy segment, there can be generation of around 11 million Jobs.

- **आगे की राह**
- **डबल शिफ्ट बर्डन:** 3Rs दृष्टिकोण, जिसमें नीति निर्माण के सभी क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा किए गए अवैतनिक देखभाल कार्य को पहचानना, कम करना और पुनर्वितरित करना शामिल है।
- **केयर इकोनॉमी:** भारत में केयर इकोनॉमी को फिर से संकल्पित करने की आवश्यकता है। यह अनुमान लगाया गया है कि देखभाल अर्थव्यवस्था क्षेत्र में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के केवल 2% के सार्वजनिक निवेश के साथ, लगभग 11 मिलियन नौकरियों का सृजन हो सकता है।

- **Recognition of Work:** For example, CII Woman Exemplar Award for women who have worked towards development initiatives in the fields of education and literacy, health, and micro enterprises, which can act as a great motivating factor for the existing as well as the aspiring female entrepreneurs.
- **Social and attitudinal Change:** Women are Humans and they must be treated as human beings, not by the gender lens.

- **काम की पहचान:** उदाहरण के लिए, शिक्षा और साक्षरता, स्वास्थ्य और सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र में विकास पहल की दिशा में काम करने वाली महिलाओं के लिए सीआईआई वुमन एक्जम्पलर अवार्ड, जो मौजूदा और साथ ही महत्वाकांक्षी महिला उद्यमियों के लिए एक महान प्रेरक कारक के रूप में कार्य कर सकता है।
- **सामाजिक और व्यवहारिक परिवर्तन:** महिलाएं इंसान हैं और उनके साथ इंसान के रूप में व्यवहार किया जाना चाहिए, न कि लैंगिक नजरिए से।

- 'God particle' or Higgs boson
- GS Paper III (Mostly for Prelims)
- **Context:** Nobel prize-winning physicist Peter Higgs, responsible for one of the greatest scientific discoveries in the last century, died at the age of 94.
- In 1964, he theorised the existence of the Higgs Boson, a fundamental force-carrying particle associated with the Higgs field.
- The Higgs field is a quantum field that gives mass to particles and exists throughout the universe.

- 'गॉड पार्टिकल' या हिग्स बोसोन
- जीएस पेपर III (ज्यादातर प्रीलिम्स के लिए)
- **संदर्भ:** पिछली शताब्दी की सबसे महान वैज्ञानिक खोजों में से एक के लिए जिम्मेदार नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी पीटर हिग्स का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- 1964 में, उन्होंने हिग्स बोसोन के अस्तित्व का सिद्धांत दिया, जो हिग्स क्षेत्र से जुड़ा एक मौलिक बल-वाहक कण है।
- हिग्स क्षेत्र एक क्वांटम क्षेत्र है जो कणों को द्रव्यमान देता है और पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है।

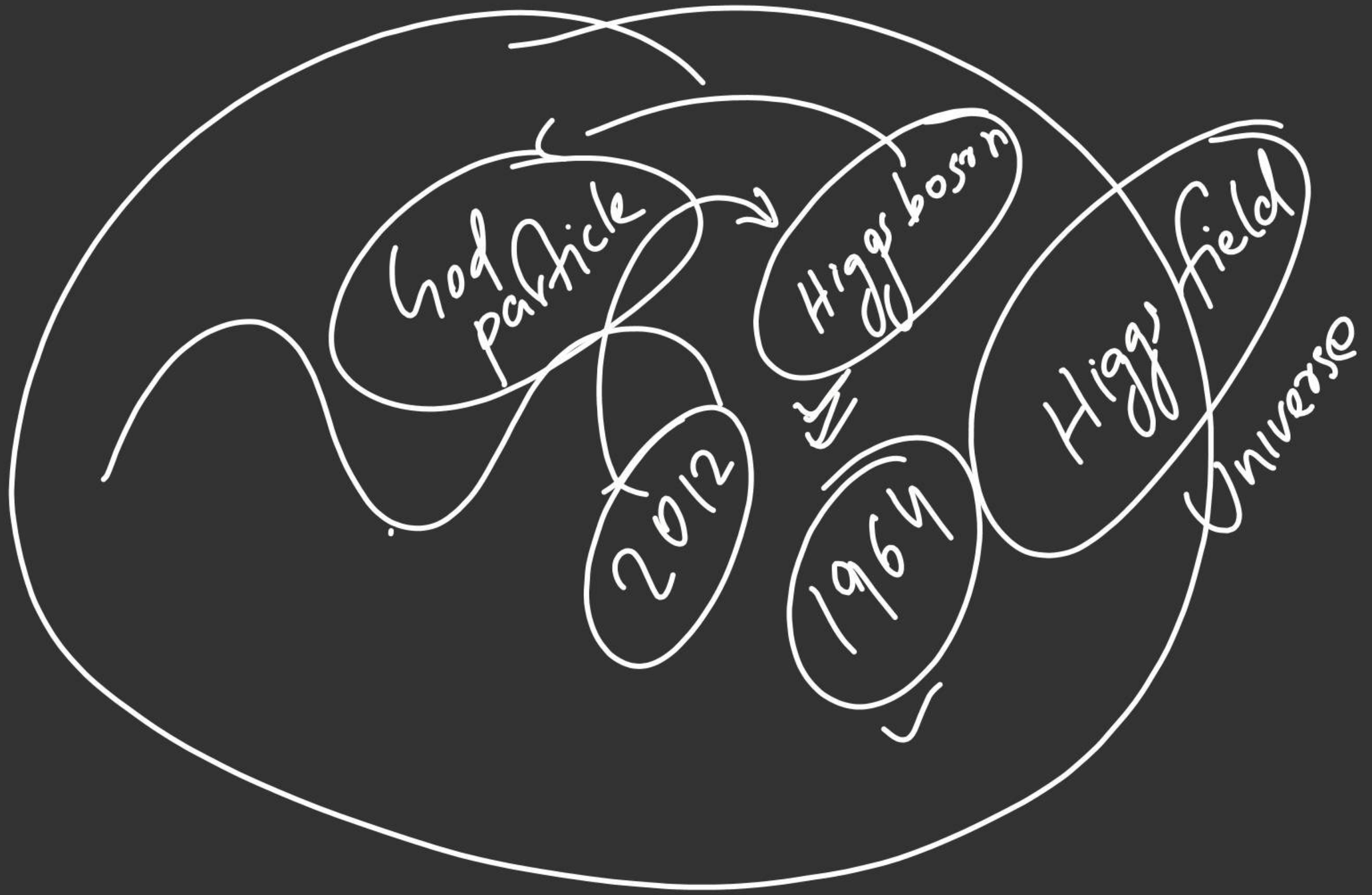
God particle
Higgs boson
2012
1964
Higgs field
Universe

- In the Higgs field, the Higgs boson acts as a wave and helps give mass to other fundamental particles through its interaction in terms of its vibration (oscillation).
- His theory was proved 50 years later when researchers at the Large Hadron Collider, the most powerful particle accelerator in the world, discovered the particle in 2012.
- Mr Higgs was awarded the Nobel prize a year later.

- हिग्स क्षेत्र में, हिग्स बोसोन एक तरंग के रूप में कार्य करता है और अपने कंपन (दोलन) के संदर्भ में अन्य मूलभूत कणों को द्रव्यमान देने में मदद करता है।
- उनका सिद्धांत 50 साल बाद साबित हुआ जब दुनिया के सबसे शक्तिशाली कण त्वरक, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के शोधकर्ताओं ने 2012 में कण की खोज की।
- एक वर्ष बाद श्री हिग्स को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- ब्रह्मांड में हर चीज़ कणों से बनी है लेकिन जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तब उनका कोई द्रव्यमान नहीं था।

- Particles make up everything in the universe but they did not have any mass when the universe began.
- They all sped around at the speed of light, according to the European Council for Nuclear Research (CERN).
- Everything we see -- planets, stars and life -- emerged after particles gained their mass from a fundamental field associated with the particle known as the Higgs boson.

- यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च (सीईआरएन) के अनुसार, वे सभी प्रकाश की गति से घूम रहे थे।
- हम जो कुछ भी देखते हैं - ग्रह, तारे और जीवन - हिग्स बोसोन नामक कण से जुड़े मौलिक क्षेत्र से कणों द्वारा अपना द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद उभरा।

❖ Strategic Petroleum Reserve:

➢ **GS Paper III (Mostly for Prelims)**

➢ India is planning to establish its first privately managed Strategic Petroleum Reserve (SPR) by 2029-30. This implies that companies managing oil reserves will have the liberty to trade stored oil.

➢ This model has already been successfully implemented in countries like Japan and South Korea.

➢ So far, India has only allowed partial trading for its existing three SPRs (located in South India, with a total capacity of

❖ सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व:

➢ **जीएस पेपर III (ज्यादातर प्रीलिम्स के लिए)**

➢ भारत 2029-30 तक अपना पहला निजी तौर पर प्रबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व (एसपीआर) स्थापित करने की योजना बना रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि तेल भंडार का प्रबंधन करने वाली कंपनियों को संग्रहीत तेल का व्यापार करने की स्वतंत्रता होगी।

➢ यह मॉडल जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में पहले ही सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है।

➢ अब तक, भारत ने अपने मौजूदा तीन एसपीआर (दक्षिण भारत में स्थित, कुल क्षमता 36.7 मिलियन बैरल) के लिए केवल आंशिक व्यापार की अनुमति दी है।

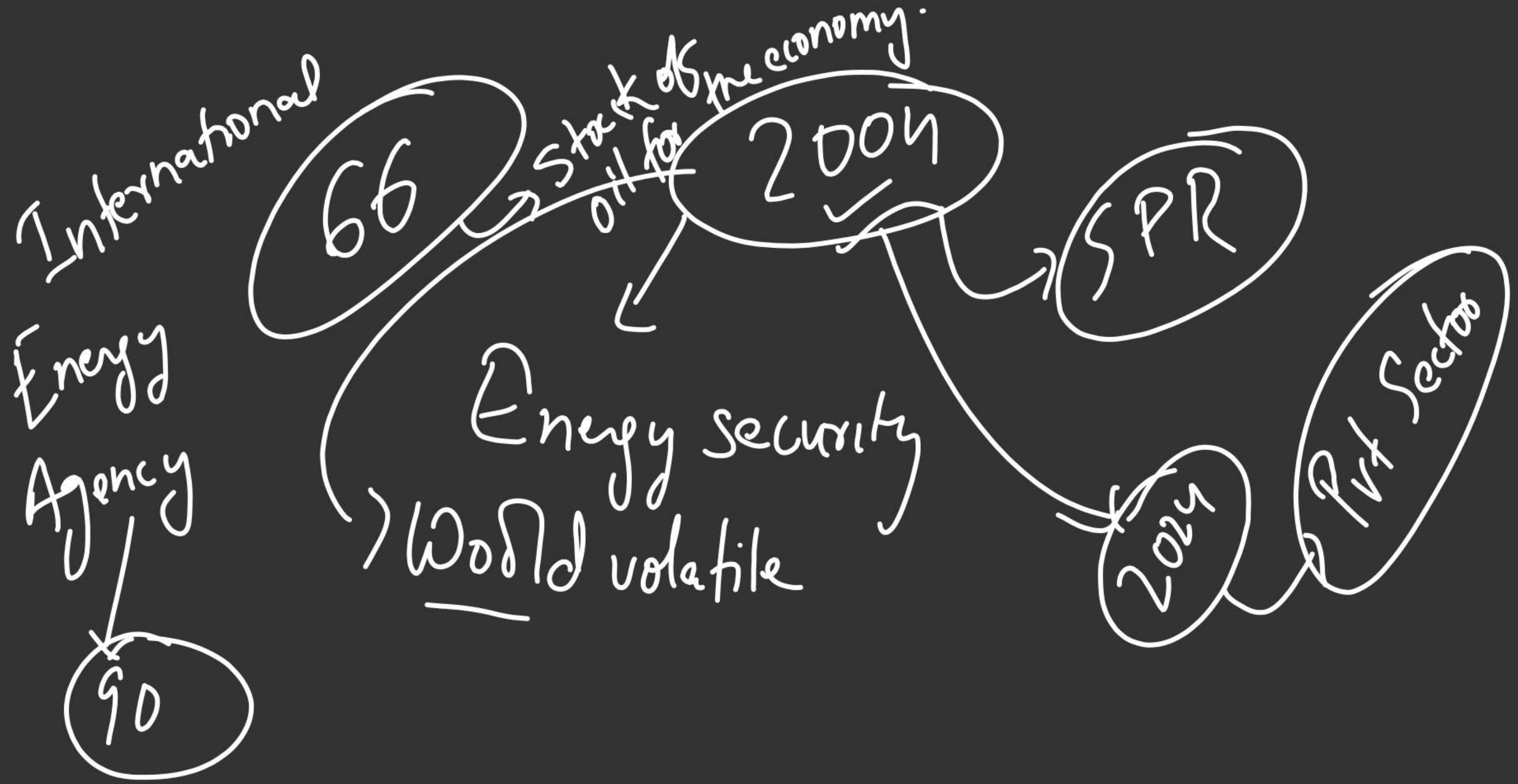

International
Enegy
Agency
66
90
stock of oil for the economy.
2004
SPR
2024
Pvt Sector
Enegy security
World volatile

- 36.7 million barrels)
- However, there are plans to establish two new SPRs – one in Padur, Karnataka, with a capacity of 18.3 million barrels, and another in Odisha with a capacity of 29.3 million barrels.
- Strategic Petroleum Reserves (SPRs) are stockpiles of crude oil that countries maintain in case of supply disruptions
- In 2004, the Indian government decided to build SPRs to ensure the country's energy security. .

- हालाँकि, दो नए एसपीआर स्थापित करने की योजना है - एक पादुर, कर्नाटक में, जिसकी क्षमता 18.3 मिलियन बैरल है, और दूसरा ओडिशा में 29.3 मिलियन बैरल की क्षमता के साथ है।
- रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (एसपीआर) कच्चे तेल के भंडार हैं जिन्हें देश आपूर्ति में व्यवधान की स्थिति में बनाए रखते हैं
- 2004 में, भारत सरकार ने देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एसपीआर बनाने का निर्णय लिया।
- सरकार ने दक्षिणी भारत में अपने तीन मौजूदा एसपीआर के आंशिक व्यावसायीकरण की अनुमति दी है, जिनकी संयुक्त क्षमता 36.7 मिलियन बैरल है।

- The government has allowed partial commercialization for its three existing SPRs in southern India, which have a combined capacity of 36.7 million barrels.
- India is trying to increase its SPR capacity to avoid such scenarios, and to qualify for membership in the International Energy Agency (IEA).
- Membership in the IEA requires having reserves equivalent to at least 90 days of oil consumption in the country, but India currently can only cover 66 days of consumption

- भारत ऐसे परिदृश्यों से बचने और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) में सदस्यता के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए अपनी एसपीआर क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।
- IEA में सदस्यता के लिए देश में कम से कम 90 दिनों की तेल खपत के बराबर भंडार होना आवश्यक है, लेकिन भारत वर्तमान में केवल 66 दिनों की खपत को कवर कर सकता है

❖ Food waste Index Report:

➢ **GS Paper III (Mostly for Prelims)**

➢ The United Nations Environment Programme (UNEP) Food Waste Index Report 2024, published in March 2024, reveals that around one billion meals are wasted worldwide daily.

➢ This is about 19% of all food produced in 2022, or 1.05 billion metric tons.

➢ The report also states that 783 million people struggled with hunger in 2022, and a third of humanity faced food insecurity

❖ खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट:

➢ **जीएस पेपर II/III (ज्यादातर प्रीलिम्स के लिए)**

➢ मार्च 2024 में प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 से

➢ पता चलता है कि दुनिया भर में प्रतिदिन लगभग एक अरब टन भोजन बर्बाद होता है।

➢ यह 2022 में उत्पादित सभी खाद्य पदार्थों का लगभग 19% या 1.05 बिलियन मीट्रिक टन है।

➢ रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2022 में 783 मिलियन लोग भूख से जूझ रहे थे और मानवता के एक तिहाई हिस्से को खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा।

- The report highlights several key findings, including:
- 60% of food waste occurs at the household level
- Food services are responsible for 28% of food waste, and retail for 12%
- Rural areas generally waste less food than urban areas
- Hotter countries tend to generate more food waste due to high consumption of perishable goods with inedible parts
- Food waste contributes substantially to climate change and biodiversity loss

- रिपोर्ट में कई प्रमुख निष्कर्षों पर प्रकाश डाला गया है, जिनमें शामिल हैं:
- 60% भोजन की बर्बादी घरेलू स्तर पर होती है
- भोजन की बर्बादी के लिए खाद्य सेवाएं 28% और खुदरा 12% के लिए जिम्मेदार हैं।
- ग्रामीण क्षेत्र आमतौर पर शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम भोजन बर्बाद करते हैं
- गर्म देशों में अखाद्य भागों के साथ खराब होने वाली वस्तुओं की अधिक खपत के कारण अधिक खाद्य अपशिष्ट उत्पन्न होता है
- भोजन की बर्बादी जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान में महत्वपूर्ण योगदान देती है

Impact

28%

→ food deprivation

→ Global warming → disposal of waste food
↳ Production of Extra food

→ loss to economy

- It accounts for close to 10% of global greenhouse gas emissions
- **About India**
- Indian households waste 78.2 million tonnes of food every year despite India housing the world's largest hunger population.
- India's per capita food waste has been estimated at 55 kg per year.
- Rural India wastes food less compared to urban areas.

- यह वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 10% हिस्सा है
- **भारत के बारे में**
- दुनिया की सबसे बड़ी भुखमरी आबादी भारत में रहने के बावजूद भारतीय परिवार हर साल 78.2 मिलियन टन खाना बर्बाद करते हैं।
- भारत में प्रति व्यक्ति भोजन की बर्बादी प्रति वर्ष 55 किलोग्राम आंकी गई है।
- शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण भारत कम खाना बर्बाद करता है।

- Out of the total food wasted in 2022, 60% happened at the household level, with food services responsible for 28 per cent and retail 12 per cent

- 2022 में बर्बाद हुए कुल भोजन में से 60% घरेलू स्तर पर हुआ, 28 प्रतिशत के लिए खाद्य सेवाएँ और 12 प्रतिशत के लिए खुदरा जिम्मेदारियाँ जिम्मेदार थीं।

❖ Places in News: Botswana

➢ Syllabus: Prelims Specific

➢ Context: Botswana's President Mokgweetsi Masisi threatened to send 20,000 elephants to Germany. The statement came after Germany, earlier this year, proposed to enact stricter limits on the import of trophies from hunting animals.

➢ Botswana is home to around the world's largest elephant population (roughly 1.3 lakh).

❖ समाचार में स्थान: बोत्सवाना

➢ पाठ्यक्रम: प्रारंभिक परीक्षा विशिष्ट

➢ संदर्भ: बोत्सवाना के राष्ट्रपति मोकग्वेत्सी मसीसी ने जर्मनी में 20,000 हाथियों को भेजने की धमकी दी। यह बयान जर्मनी द्वारा इस साल की शुरुआत में शिकार करने वाले जानवरों से ट्रॉफियों के आयात पर कड़ी सीमाएं लागू करने के प्रस्ताव के बाद आया है।

➢ बोत्सवाना दुनिया की सबसे बड़ी हाथियों की आबादी (लगभग 1.3 लाख) का घर है।

DEMOCRATIC
REPUBLIC
OF THE CONGO
TANZANIA
INDIAN
OCEAN
ANGOLA
MALAWI
ZAMBIA
MOZAMBIQUE
ZIMBABWE
MADAGASCAR
BOTSWANA
NAMIBIA
GABORONE
ESWATINI
LESOTHO
SOUTH
AFRICA
ATLANTIC
OCEAN
1.3 lakh
elephants

Linyanti River

KHAN GLOBAL STUDIES

Most Trusted Learning Platform

THANKS FOR WATCHING